बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 190 ● नई दिल्ली ● वीरवार 14 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर, राजनाथ सिंह ने छोटा किया अपना काफिला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काफिले का आकार लगभग आधा कर दिया है।राजनाथ सिंह का यह कदम तब आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच नागरिकों से सात अपीलें की थीं। इन अपीलों का मकसद आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर देश की आर्थिक मजबूती में योगदान देना था। पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। उन्होंने इस दौरान वैश्विक ऊर्जा-पुरवल और बढ़ती कीमतों के असर को भी रेखांकित किया था।

एलजी तरनजीत सिंह संधू ने कुलपतियों के साथ की बैठक, एआई और रिसर्च आधारित शिक्षा बढ़ाने को कहा

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की यूनिवर्सिटीज को सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि रिसर्च और सामाजिक बदलाव के केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को अब दिल्ली की असली समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उपराज्यपाल ने बुधवार को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों और निदेशकों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा, रिसर्च और तकनीक के जरिए दिल्ली के विकास को नई दिशा देने पर चर्चा हुई। एलजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के तहत शैक्षणिक संस्थानों को इनोवेशन, रिसर्च और सामाजिक बदलाव का केंद्र बनना होगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों से कहा कि वे केवल डिग्री देने तक सीमित न रहें, बल्कि नए अनुसंधान की भावना के साथ दिल्ली की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजें।

वायु प्रदूषण, ट्रैफिक से जुड़ी चुनौतियों पर तैयार करें रिसर्च आधारित समाधान

संधू ने खास तौर पर वायु प्रदूषण, ट्रैफिक और शहरी परिवहन, मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों पर रिसर्च आधारित समाधान तैयार करने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों में मौजूद रिसर्च क्षमता का सीधा लाभ शहर और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए।

छात्रों की सामाजिक भागीदारी बढ़ाएं

बैठक में छात्रों की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एलजी ने कहा कि एनएसएस, एनसीसी और गांव गोद लेने जैसी योजनाओं के जरिए छात्रों को समाज से जोड़ा जाए, ताकि वे जिम्मेदार नागरिक, इनोवेटर और रोजगार पैदा करने वाले युवा बन सकें। उन्होंने एआई और नई तकनीकों के इस्तेमाल को भविष्य की जरूरत बताते हुए कहा कि दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ को टेक्नोलॉजी आधारित और भविष्य के लिए तैयार संस्थान बनाना जरूरी है। एलजी ने सभी संस्थानों से समयबद्ध और ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि शिक्षा और रिसर्च का फायदा सीधे दिल्ली के लोगों तक पहुंच सके।

खुद को हिंदू साबित करने के लिए एक दीपक ही काफी, मंदिर जाने की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदुत्व जीवनशैली है और किसी हिंदू को हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या कोई अनुष्ठान करना अनिवार्य नहीं है, यहां तक कि घर के अंदर दीपक जलाना भी आस्था साबित करने के लिए पर्याप्त है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और दाऊदी बोहरा समुदाय सहित कई धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की.पंद्रहवें दिन सुनवाई शुरू होने पर हस्तक्षेपकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डॉ. जी मोहन गोपाल ने कहा कि धार्मिक समुदायों के भीतर से सामाजिक न्याय की मांग उठ रही है. उन्होंने कहा, ''हिंदू धर्म को एक धार्मिक श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया था.उसके बाद 1966 में यह माना गया कि हिंदू वह है जो धर्म और दर्शन के सभी मामलों में वेदों को सर्वोच्च मानता है.उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा. हममें से किसी ने भी ऐसा कभी नहीं कहा. उन्होंने कहा, ''मेरा वेदों के प्रति अत्यंत आदरभाव है, लेकिन क्या यह सच है कि आज हिंदू कहलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक और दार्शनिक मामलों में वेदों को सर्वोच्च मानता है? उनकी दलील का जवाब देते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, ''इसीलिए हिंदुत्व को जीवनशैली कहा जाता है.हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या कोई अनुष्ठान करना अनिवार्य नहीं है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हो सकता है कि किसी को कर्मकांडी होने की जरूरत नहीं है और आस्था रखने वाले लोगों के रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकता. सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक दीपक भी जलाता है, तो यह उसके धर्म को साबित करने के लिए पर्याप्त है. न्यायालय ने इससे पहले टिप्पणी की थी कि यदि व्यक्ति किसी संवैधानिक अदालत के समक्ष हर धार्मिक प्रथा या धर्म से संबंधित मामलों पर सवाल उठाना शुरू कर दें, तो सैकड़ों याचिकाएं दायर की जाएंगी और इसके कारण हर धर्म टूट जाएगा. सितंबर 2018 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए शबरिमला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, और फैसला सुनाया था कि सदियों पुरानी हिंदू धार्मिक प्रथा अवैध और असंवैधानिक है.

दिल्ली में मानसून से पहले सरकार की टेंशन बढ़ी, जलभराव के हॉटस्पॉट बढ़कर हुए 448; इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय

नई दिल्ली। दिल्ली में जलभराव रोकने के लिए सरकार इस बार भी चुनौती बढ़ रही है। जलभराव के मामले में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 448 हुई है। इसमें पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जलभराव वाले सबसे अधिक स्थान मिले हैं। इससे पहले 2025 में 410 और 2024 में जलभराव के मामले में हॉटस्पॉट की संख्या 310 रही थी। हालांकि सरकार ने इन सभी पॉइंट के लिए अभियंताओं की तीन सदस्य टीम बनाई है। हर प्वाइंट के लिए कनिष्ठ अभियंता की जिम्मेदारी तय की गई

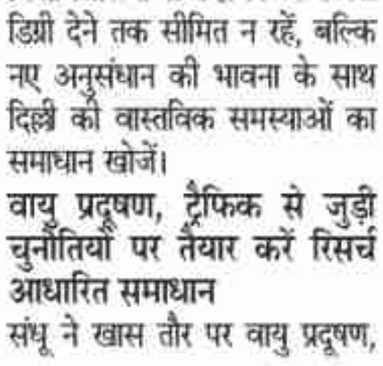

है। विभाग ने आदेश जारी कर यह भी साफ किया है कि इन पॉइंट पर जलभराव हुआ तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सरकार ने अभी से यहां जलभराव रोकने की लिए काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस साल के सर्वे में सामने आया है कि ड्रेनेज ओवरफ्लो और सड़कों पर पानी जमा होने की सबसे गंभीर समस्या पूर्वी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के इलाकों में यादा है।

इन दोनों ही क्षेत्रों में जलभराव वाले सबसे अधिक स्थान चिह्नित किए गए हैं। घनी आबादी और संकरी गलियों वाले इन इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की पुरानी रूपरेखा और समय पर गाद न निकालना इस संकट का मुख्य कारण माना जा रहा है। यदि पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में जलभराव की स्थिति साल-दर-साल और विकराल होती जा रही है। तीन सालों में हॉटस्पॉट की संख्या में हुई 138 अंकों की बढ़ोतरी दर्शाती है कि मानसून से पहले नालों की सफाई में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। लगातार गंभीर होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार प्रशासनिक स्तर पर कमर कस ली है। जलभराव की समस्या से तुरंत निपटने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। यह टीम मानसून के दौरान और उससे पहले ग्राउंड जीरो पर तैनात रहकर ड्रेनेज की रुकावटों को दूर करेगी, ताकि वर्षा होते ही पानी की निकासी सुनिश्चित की जा सके।

दिल्ली के इस इलाके में सड़क पर गाड़ी पार्क करना पड़ेगा भारी, कटेगा 25 हजार तक का चालान

नई दिल्ली। दिल्ली कैंट इलाके में अगर आप भी सड़क किनारे अपनी कार या बाइक पार्क करके घंटों के लिए भूल जाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए. मनमानी पार्किंग करने वालों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर ट्रैफिक जाम बढ़ाने वालों पर कैंट बोर्ड ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद, आपकी एक छोटी सी गलती आपको हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान करा सकती है. कैंट क्षेत्र के सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार और शास्त्री बाजार जैसे व्यस्त इलाकों में लंबे समय से अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है. लोग घंटों तक अपना वाहन सड़क पर ही खड़ा छोड़ देते हैं, जिससे पूरे इलाके की यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है और आम लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ता है. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कैंट बोर्ड ने पहली बार एक विस्तृत टोइंग पॉलिसी तैयार की है. इसके तहत, अब नियम तोड़कर नो-पार्किंग में खड़े किए गए वाहनों को क्रेन से तुरंत मौके से हटा लिया जाएगा. इसके बाद वाहन मालिकों से टोइंग चार्ज (वाहन हटाने का खर्च) के साथ-साथ कई तरह के भारी शुल्क वसूले जाएंगे. नई व्यवस्था के तहत वाहन जितने दिन तक पुलिस या बोर्ड के स्टोरेज यार्ड में खड़ा रहेगा, मालिक को उतना ही अधिक शुल्क देना होगा. अधिकारियों के मुताबिक, अगर वाहन को छुड़ाने में कुछ दिनों की भी देरी हुई, तो टोइंग और स्टोरेज चार्ज मिलाकर कुल खर्च 20 से 25 हजार रुपये तक पहुंच सकता है

दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, कटौती के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरा

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (13 मई) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. केजरीवाल ने एक तरफ पेपर लीक मामलों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल और गैस खरीद को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार देशवासियों से पेट्रोल-डीजल और गैस बचाने की अपील कर रही है, लेकिन दूसरी ओर रूस से सस्ती गैस और तेल लेने से इनकार कर रही है. केजरीवाल ने दावा किया कि यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि अभी खबर आई है कि रूस से गैस लेकर एक जहाज भारत की ओर आ रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उसे रोक दिया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में तेल और गैस की कमी की बात हो रही है तो रूस से खरीद क्यों नहीं की जा रही. उन्होंने कहा, मोदी जी देशवासियों से कह रहे हैं कि स्कूटर, बाइक इस्तेमाल मत करो. कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ. लेकिन दूसरी तरफ रूस तेल और गैस देने को तैयार है और हम मना कर रहे हैं. आखिर क्यों? क्या ट्रंप ने मना किया है? केजरीवाल ने कहा कि 140 करोड़ लोगों का हित यादा जरूरी है, न कि ट्रंप को खुश करना. उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश ट्रंप की हर बात नहीं मान रहा, लेकिन भारत सरकार झुकती दिखाई दे रही है. आप प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर वे

अंतरराष्ट्रीय दबाव झेलने की क्षमता नहीं रखते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा, अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए. इस देश में ऐसे लोग हैं जो ट्रंप की आंखों में आंख डालकर जवाब दे सकते हैं. केजरीवाल ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का बड़ा बाजार है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि अगर भारत चाहे तो अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बना सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने ह्वश्वञ्ज समेत कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में 93 पेपर लीक हुए और करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया. उन्होंने कहा, ÷जब से मोदी सरकार आई है तब से कुल 93 पेपर लीक हुए हैं. करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन पेपरों में बंद था. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अधिकतर पेपर लीक बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं और इस बार नीट पेपर लीक का केंद्र राजस्थान बना. केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हर बार पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने कहा, 2017, 2021 और 2024 में पेपर लीक हुए थे. उस समय भी सीबीआई को जांच दी गई थी. क्या सीबीआई ने कुछ किया? इस बार भी जांच सीबीआई को दी गई है. क्या सीबीआई कुछ करेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो देश में पेपर लीक करा रहे हैं. केजरीवाल ने युवाओं से सड़क पर उतरने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि अगर युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो हर बार पेपर लीक होते रहेंगे. उन्होंने कहा, अगर नेपाल और बांग्लादेश के जेन जेड सरकार बदल सकते हैं तो क्या हमारे देश के जेन जेड पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकते? उन्होंने युवाओं से कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर नाराजगी दिखाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आंदोलन करना पड़ेगा. केजरीवाल ने केंद्र सरकार की कटौती और बचत वाली अपीलों को दिखावा बताया. उन्होंने कहा कि देश के लोगों से त्याग करने को कहा जा रहा है, जबकि सरकार खुद सस्ते तेल और गैस के विकल्प छोड़ रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में कूटनीति यही कहती है कि जहां से सस्ता तेल और गैस मिले, वहां से खरीदना चाहिए.

1971 का कर्ज

1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारतीय हमलों से बचाने के लिए ईरान ने पाकिस्तानी सैन्य विमानों और संसाधनों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पांच दशक बाद पाकिस्तान उसी एहसान का बदला चुकाता दिखाई देगा। अब आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने सैन्य ठिकानों पर सुरक्षित शरण दी। इस तरह इस्लामाबाद ने तेहरान का पुराना कर्ज तो उतार दिया है लेकिन अब वह खुद संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की जटिल कूटनीतिक राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के दावे वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि नूर खान वायुसेना अड्डा राजधानी के अत्यंत व्यस्त और आबादी वाले हिस्से में स्थित है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां किसी भी बड़े सैन्य बेड़े या विमानों को छिपाकर रखना संभव ही नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने भी अब तक सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार ईरान ने संभावित खतरे को देखते हुए अपने कुछ नागरिक विमानों को पड़ोसी अफगानिस्तान की ओर भेजा। अफगान नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महान एयर का एक विमान संघर्ष तेज होने से पहले काबुल पहुंचा था और बाद में सुरक्षा कारणों से उसे हेरात स्थानांतरित कर दिया गया। बताया गया कि अफगान क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमलों की खबरों के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि काबुल हवाई अड्डा भी संभावित निशाना बन सकता है। इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया के जानकारों को 1971 के दौर की याद दिला दी है। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व वाला ईरान पाकिस्तान का प्रमुख समर्थक बनकर सामने आया था। तेहरान ने इस्लामाबाद को हेलिकॉप्टर, ईंधन, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के कलपुर्जे उपलब्ध कराए थे। कई रिपोर्टों में यह उल्लेख मिलता है कि पाकिस्तान के कुछ सैन्य विमानों ने ईरानी वायुसेना अड्डों पर शरण ली थी। बाद में सार्वजनिक हुए अमेरिकी दस्तावेजों से पता चला कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन प्रशासन ने पर्दे के पीछे ईरान को पाकिस्तान की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया था। उस दौर में अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान को कमजोर होने से बचाना चाहते थे। शीत युद्ध के समय ईरान और पाकिस्तान दोनों सोवियत विरोधी सैन्य गठबंधन सेंटो के सदस्य थे और निक्सन प्रशासन इन्हें क्षेत्र में सोवियत प्रभाव को रोकने वाले महत्वपूर्ण साझेदार मानता था। पांच दशक बाद वैश्विक राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। आज ईरान अमेरिका का प्रमुख पश्चिम एशियाई प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, जबकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में चीन का सबसे करीबी सुरक्षा सहयोगी बन चुका है। चीन ने हाल के समय में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराने में पाकिस्तान की भूमिका को सार्वजनिक सराहना भी की है। इस बदलती परिस्थिति में पाकिस्तान का संतुलन साधना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। पाकिस्तान एक ओर चीनी सैन्य उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर है। रिपोर्टों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के प्रमुख हथियार आयात का लगभग अस्सी प्रतिशत हिस्सा चीन से आया। वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद अमेरिका के साथ अपने सैन्य और खुफिया संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है, जो बराक ओबामा प्रशासन के दौरान काफी कमजोर पड़ गए थे। पाकिस्तानी अधिकारी लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि तेहरान के साथ उनके संबंध किसी गुप्त सैन्य सहयोग की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रचनात्मक कूटनीति का हिस्सा हैं। पाकिस्तान समय समय पर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी करता रहा है। उसका दावा है कि दोनों देशों के साथ कार्यकारी संबंध बनाए रखने की उसकी क्षमता क्षेत्रीय तनाव कम करने में सहायक हो सकती है। इसके बावजूद अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक प्रभावशाली हिस्से में पाकिस्तान को लेकर संदेह अब भी गहराई से मौजूद है। अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी की स्मृति आज भी अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर भारी पड़ती है। अमेरिकी अधिकारी और सांसद लंबे समय से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के कुछ तत्वों पर इस्लामी उग्रवादी संगठनों के साथ व्यावहारिक संबंध रखने के आरोप लगाते रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को लगातार नकारता आया है। ताजा आरोपों ने अमेरिकी संसद में भी नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान द्वारा ईरान को सैन्य सहायता या शरण देने की खबरें सही साबित होती हैं, तो अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ के रूप में इस्लामाबाद की भूमिका का पूरी तरह पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति में पुराने रिश्ते, सामरिक हित और बदलते वैश्विक गठबंधन आज भी गहराई से प्रभाव डाल रहे हैं। बहरहाल, विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान पर आंख मूंदकर भरोसा करना अमेरिका सहित कई देशों के लिए पहले भी भारी पड़ चुका है। हाल के वर्षों में अमेरिकी रणनीतिक और सुरक्षा रिपोर्टों में भी यह संकेत दिया गया था कि पाकिस्तान की नीतियां भविष्य में अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष चुनौती बन सकती है। कुछ विश्लेषकों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया है जिनके फैसले क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकते है और अमेरिकी हितों के लिए संकट खड़ा कर सकते है। यही कारण है कि वाशिंगटन में यह राय मजबूत होती जा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सामरिक या कूटनीतिक साझेदारी में अमेरिका को अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी।

राजनीतिक विमर्श का जरिया बनी झालमुढ़ी वालों के फिरेंगे दिन

पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आ चुके है। शुभेंदु अधिकारी की अगुआई में राज्य में नई सरकार बन चुकी है। ममता बनर्जी की सरकार इतिहास के पन्नों में सिमट गई है। यूं तो हर चुनाव अभियान के साथ तमाम घटनाएं, इतिहास में समाती रहती है। उनमें से कुछ का प्रभाव बरसों तक रहता है। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव अभियान में एक घटना ऐसी घटी, जिसने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के वोटरों पर अमिट छाप छोड़ी, बल्कि बांग्ला खान-पान और संस्कृति से उन लोगों को भी परिचित करा दिया, जो उससे अब तक सर्वथा अपरिचित थे। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, समूचे बिहार, झारखंड और उड़ीसा में झालमुढ़ी खानपान का अभिन्न अंग है। झालमुढ़ी में दो शब्द है। पहला शब्द है झाल, जिसका मतलब होता है तीखा, ऐसा तीखापन, जिसका असर सिर्फ जुबान पर ही नहीं महसूस हो, बल्कि जुबान की सिसियाहट के साथ नाक के रास्ते भी हल्की झलन का अहसास है। इस शब्द के मूल में है मुढ़ी, जिसे कहीं मुढ़ी तो कहीं मुरमुरा तो कहीं मुर्रा कहा जाता है। इसमें प्याज, टमाटर, नमकीन, हरी मिर्च, सरसों तेल, नमक और भुना जीरा आदि डालकर जो मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे झालमुढ़ी या झालमुड़ी कहा जाता है। इसी झालमुढ़ी को झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में 19 अप्रैल के दिन चुनाव प्रचार के बीच सड़क पर उतर कर मात्र दस रूपए में खरीदकर जब प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद महिलाओं-बच्चों के साथ मिलकर खाया था। इसके साथ ही झालमुढ़ी इंटरनेट सर्च की दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गई। झालमुढ़ी में कई बार भुने हुए चने भी मिलाए जाते है तो कई बार भीगे हुए कच्चे चने तो कई बार उस चने से बनी घुघनी। जिन्हें घुघुनी के बारे में पता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि भीगे हुए चने को जीरा, हरी मिर्च के सरसों तेल में छौंक लगाने के बाद सूखा और कई बार प्याज-टमाटर आदि मिलाकर मसालों को साथ भी पकाया जाता है। पश्चिम बंगाल ही क्यों, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मुढ़ी को विशेषकर शाम की चाय के वक्त खाया जाता है। इन इलाकों के स्कूलों, कॉलेजों के बाहर, कचहरियों में स्टेशन के सामने झालमुढ़ी के ठेले और खोमचे खूब दिख जाएंगे। विशेषकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुढ़ी या मुड़ी तैयार की जाती है। इसके लिए पहले धान को उबाला जाता है, फिर उसे सुखाकर जो चावल निकाला जाता है, उसे भूनने के बाद मुढ़ी या मुड़ी का रूप मिलता है। इस तरह से कह सकते है कि मुढ़ी या मुड़ी सेला चावल का भुना हुआ रूप है। पश्चिम बंगाल और मिथिलांचल में तो मुढ़ी को पकौड़े के साथ भी खाया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो इसे आलूचप के साथ विशेष रूप में पसंद किया जाता है। अब सवाल उठ सकता है कि आलूचप क्या होता है। दरअसल उबले आलू को मसलकर उसमें नमक, मसाले आदि मिलाकर उसकी टिक्की को बनाया जाता है। फिर उसे बेसन में डुबोकर छाना जाता है। इसे ही आलूचप कहा जाता है। वैसे आलूचप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में खूब प्रचलित है। विशेषकर शाम की चाय के वक्त। झालमुढ़ी का पश्चिम बंगाल की राजनीति से खास रिश्ता है। राजनीतिक, चुनावी आदि चर्चाओं में चाय के साथ सहज उपलब्ध झालमुढ़ी ही होती है। कई बार सिर्फ मुढ़ी भी खाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शादी-विवाह मुंडन-जनेऊ के हल्दी और मंडप बनाने के दिन विशेषरूप से लोगों को सिर्फ मुढ़ी मिठाई या गुड़ के साथ नास्ते में दी जाती है। बहुत कम लोग जानते है कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कोलकाता के एक मैदान पर ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो के संग झालमुढ़ी खाया था। इसके जरिए उन्होंने अपनी विजय, भाजपा से बेफिक्री और अपने लोगों को संदेश दिया था। उन्नीस अप्रैल को झाड़ग्राम में झालमुढ़ी खरीदते वक्त पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी को यह पता था कि नहीं, लेकिन उन्होंने इसके जरिए इतिहास रच दिया। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े संचारक यानी कम्युनिकेटर थे। प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े संचारक यानी कम्युनिकेटर हैं। मात्र दस रूपए की झालमुढ़ी के जरिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के आम लोगों के दिलों तक जगह बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी का संदेश सीधे हर घर तक पहुंचा दिया। जिन इलाकों में झालमुढ़ी खाई जाती है, उन इलाकों में देखेंगे तो हर राजनीतिक सम्मेलन, रैली आदि के दौरान बाहर इसके ठेले और खोमचे लगे होते हैं। कई बार नेताओं के इंतजार में वक्त काटने तो कई बार तात्कालिक भूख मिटाने का जरिया यह झालमुढ़ी ही होती है। स्कूलों, कॉलेजों और कचहरियों के आसपास झालमुढ़ी और चने-चबेने के खोमचे और ठेले आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुतायत से मिल जाएंगे। हाट-बाजार में भी शाम की चाय के वक्त का इन इलाकों का सबसे आसानी से सस्ते में उपलब्ध और पसंदीदा स्नैक यह झालमुढ़ी ही है। झालमुढ़ी आम लोगों और आम दुकानदारों से जुड़ने का भी सबसे बड़ा जरिया है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने झाड़ग्राम में सड़क किनारे की झालमुढ़ी की दुकान को चुना और महज दस रूपए की झालमुढ़ी के ठोंगे यानी लिफाफे के जरिए पश्चिम बंगाल के करोड़ों दिलों तक जगह बना ली। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है।

सम्पादकीय...

फ़ासीवाद पर परिचर्चा - हिटलर का भूत हिंदुस्तान में समा गया है?

प्रारम्भिक वक्तव्य देते हुए इसकफ के राज्य महासचिव रवीन्द्र नाथ राय ने कहा पूंजीवाद का विकृत रूप फासीवाद है। वह संसद को, संविधान को लोकतांत्रिक अधिकारों सबको नष्ट कर देता है। हिटलर घृणा फैलाता था। एक नस्ल की सर्वोच्चता की बात किया करता था। रेडियो से अपना भाषण प्रसारित करता था। ट्रेड यूनियन आंदोलन से, कम्युनिस्टों से नफरत करता था। अति महत्वाकांक्षा के कारण पूरी दुनिया के साथ साथ जर्मनी को बर्बाद कर डाला। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद फासीवाद का उभार हुआ। हमें देखना है कि क्या भारत में भी वैसी ही परिस्थितियां तो नहीं कायम हो गई है? हमें देखना है कि कहीं हिटलर का भूत हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं आकर समा गया है? फासिस्ट किसी एक धर्म को अपने देश के अंदर का दुश्मन बनाता है। ऐप्सो के राज्य महासचिव अनीश अंकुर ने बताया फासीवाद की हार में सबसे बड़ी भूमिका सोवियत संघ और चीन ने निभाई। यदि आज से अस्सी वर्ष पूर्व जर्मनी, जापान और इटली के फासीवादी गठजोड़ की पराजय हुई तो इसके पीछे सोवियत संघ के दो करोड़ सत्तर लाख और चीन के दो करोड़ चालीस लाख मारे गए। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था उनलोगों ने सबसे ज्यादा फासीवाद का कहर झेला। द्वितीय विश्वयुद्ध में लगभग साढ़े आठ करोड़ लोग मारे गए जिसमें से 73 प्रतिशत अकेले रूस चीन और एशिया-अफ्रीका के लोगों को शहादत देनी पड़ी थी। इंग्लैंड - अमेरिका के सिर्फ 1 प्रतिशत नुकसान हुआ था। लेकिन आज इतिहास से रूस और चीन के अकल्पनीय शहादत को मिटाया जा रहा है। एस.यू.सी.आई के राजकुमार चौधरी के अनुसार जब पूंजीवाद पूरी तरह प्रतिक्रियावादी और प्रतिक्रांतिकारी हो जाता है, जिन मूल्यों का उसने सृजन किया हुआ था उसे ही खत्म कर देना चाहता है तब उसी अवस्था में फासीवाद का जन्म होता है। पूंजीवाद अब मरणासन्न अवस्था में आ गया है। उसका एक दिन भी रहना समाज के लिए खतरनाक है। फासीवाद कोई व्यक्ति, कोई पार्टी भी फासीवाद नहीं लाता है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के संकट के कारण फासीवाद लाता है। जब तक पूंजीवाद बरकरार रहेगा तब तक फासीवाद भी रहेगा। इसके लिए व्यापक मोर्चा बनाकर लड़ना पड़ेगा। पटना विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रो सुधीर कुमार ने कहा फासीवाद के अंदर तर्क शक्तियों को कमजोर किया जाता है। सब अधिकार हमारे हाथ में नियंत्रित हो। ऐसा कोशिश किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर काम करना होगा। हमें भारत के अंदर भी काम करना होगा। यह लोगों की भावनाओं को जगाकर काम करता है। यह समाज के अन्दर वर्चस्व कायम करने के लिए काम करता है। मुसोलिनी कहा करता था सब कुछ देश है। सामाजिक कार्यकर्ता विजयकांत सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा -फासीवाद घोर जनतंत्र विरोधी होता है। यदि आप पब्लिकली उसके खिलाफ बोलते है तो पुलिस या एजेंसी आपके दरवाजे पर चली आती है। फॉसिज्म के खिलाफ लड़ाई के मोर्चा दिशा छात्र संगठन के अजीत ने दिल्ली-नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फासीवाद का मुकाबला भारत के पचपन करोड़ मजदूर ही करेगा। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए भाकपा नेता रामलला सिंह ने कहा 1917 की सोवियत क्रांति ने इतिहास बदल डाला।

चिंता का सबब एनसीआरबी के आंकड़े

जाहिर है, पुलिस व्यवस्था को अब डंडे से ज्यादा डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा एनालिटिक्स की जरूरत है। वास्तव में, एनसीआरबी के आंकड़े समाज के उस अंधेरे पक्ष को उजागर करने वाले होते हैं, जिनकी अनदेखी के परिणाम समाज को पतन की ओर धकेलने वाले हो सकते हैं। इन आंकड़ों से इसका भी संकेत मिलता है कि शासन-प्रशासन को किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। बदलते वक्त और समाज के आचरण से अपराध का स्वरूप और प्रवृति बदल रही है। इस बिंदु पर भी जिम्मेदारों का ध्यान देने की जरूरत है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट, जिसमें साल 2024 में हुए अपराधों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले है। रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति 17 मिनट में किसी न किसी की हत्या, हर पांच मिनट में किसी न किसी का अपहरण और हर 18 मिनट में किसी न किसी से बलात्कार हो रहा है। धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध तो हर दो मिनट में हो रहे है। डिजिटल क्रांति के बाद तो साइबर अपराध की बाढ़ आ गई है और इन्हें नियंत्रित करने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे है। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में भारत में कुल संज्ञेय अपराधों में कमी दर्ज की गई लेकिन साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, ड्रग ओवरडोज मौतों और सामाजिक संकट से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई। 2024 में देश में कुल 58.86 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए। 2023 में यह संख्या 62.41 लाख थी। यानी कुल अपराधों में लगभग 6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। देश के छात्रों से जुड़ा आंकड़ा गंभीरता से सोचने को विवश करता है। देश में छात्र आत्महत्या के मामलों ने 2024 में नया चिंताजनक रिकॉर्ड बना दिया है। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में कुल 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की, जो 2023 के 13,892 मामलों की तुलना में 4.3 प्रतिशत अधिक है। चिंता की बात यह है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब देश में कुल आत्महत्या के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। एनसीआरबी के मुताबिक, 2023 में कुल 1,71,418 आत्महत्या के मामले सामने आए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 1,70,746 रह गई। मनोचिकित्सकों के अनुसार परीक्षा का दबाव, कड़ी प्रतिस्पर्धा, अभिभावकों की अपेक्षाएं, करियर की चिंता और सोशल मीडिया का प्रभाव छात्रों पर भारी मानसिक दबाव बना रहे है। वहीं कई छात्र अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और गहरे भावनात्मक तनाव से जूझ रहे होते हैं लेकिन समय पर उनकी पहचान नहीं हो पाती। हमें स्कूलों और कॉलेजों में शुरुआती पहचान, बिना भेदभाव वाली काउंसलिंग और मजबूत मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली की तत्काल जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को मुख्यधारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों और अभिभावकों को भी इस बात के लिए प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए कि वे छात्रों में तनाव और अवसाद के शुरुआती संकेत पहचान सकें और ऐसा माहौल बनाएं जहां छात्र बिना डर और शर्म के मदद मांग सकें। हैरानी की बात यह भी है कि शांत समझा जाने वाला राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार छठे साल शीर्ष पर बना हुआ है। बलात्कार के मामले में यह पहले स्थान पर, जबरन गर्भपात में दूसरे और भ्रूण हत्या में तीसरे स्थान पर है। विवाह के लिए महिलाओं के अपहरण के मामलो में भी राजस्थान चौथे नंबर पर है। इस अपराध में बिहार टॉप, यूपी दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। बिहार 'पकड़वा विवाह' के लिए भी बदनाम है, जिसमें पुरुषों का अपहरण कर जबरन शादी कर दी जाती है। यदि प्रति लाख आबादी के लिहाज से हत्या की दर का विश्लेषण किया जाए तो झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य टॉप पर है और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा और अपराधों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाला राज्य 12वें स्थान पर। इस मामले में मध्यप्रदेश छठे और राजस्थान सातवें पायदान पर खड़ा है। 2023 में साइबर अपराध के 86,420 मामले दर्ज हुए थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,01,928 हो गई। यानी लगभग 17.9 फीसदी की वृद्धि हुई। कुल साइबर अपराधों में लगभग 72.6 फीसदी मामले साइबर फ्रॉड से जुड़े थे। 2024 में मेट्रो शहरों में लगभग 35,000 साइबर अपराध मामले दर्ज हुए। 1.2 लाख से अधिक मामले जांच के लिए लंबित रहे। लगभग 75,000 मामले ट्रायल में लंबित है। इन आंकड़ों के आलोक में बात करें तो देश में ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान और फिनटेक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही है। उपभोक्ता सुरक्षा तंत्र कमजोर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर फिर गंभीर सवाल खड़े हुए है। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में शीर्ष पर रही है। 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 मामले दर्ज किए गए जो 2023 में 13,366 थे। तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे है। दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ 1,267 अपराध दर्ज किए गए। दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों की दर प्रति लाख आबादी पर 110 मामले रही, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दरों में से एक रही। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा, जहां 2024 में 5,875 मामले दर्ज किए गए, यह संख्या 2023 के 5,738 मामलों से ज्यादा है। दूसरी तरफ, देश में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। 2024 में कुल 32,602 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 16.9 फीसदी ज्यादा है। भारत में अपहरण और जबरन उठा ले जाने की घटनाएं पिछले एक दशक में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। हाल ही में भोपाल में एक आईएएस एकेडमी की निदेशक के अपहरण और 1.89 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है। आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1953 से 2024 के बीच देश में कुल 20 लाख से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन सात दशकों के कुल मामलों का 54 फीसदी हिस्सा (11.24 लाख केस) केवल पिछले 11 वर्षों (2013-2024) में दर्ज हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, कुल अपराधों में अपहरण की हिस्सेदारी 1953-62 में 1.01 फीसदी थी, जो 2013-24 के दौरान बढ़कर 3.04 फीसदी तक पहुंच गई है। फिरौती के लिए किए जाने वाले संगठित अपहरण कुल मामलों का केवल 0.7 फीसदी ही है। राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे स्थान पर रहा करता था, लेकिन 2024 के आंकड़ों में बिहार शीर्ष छह राज्यों में सबसे नीचे दर्ज किया गया है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अपराध घटने के बावजूद बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,87,702 मामले दर्ज हुए। यह जो 2023 के 1,77,335 मामलों से 5.8 फीसदी ज्यादा है। थोड़ी सुकून वाली बात यह है कि नवीनतम आंकड़ों में 2023 की तुलना में कई तरह के संगीन अपराधों में कमी आई है। कुछ विशेषज्ञ इसकी वजह नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होना बता रहे है, जिसमें संज्ञेय अपराधों की लिस्ट से कई अपराध हटा दिए गए है। आत्महत्या के मामलों में मामूली कमी भी संतोषजनक है, पर विद्यार्थियों और बेरोजगारों की खुदकुशी के मामले बढ़ता रोजगार संकट, शिक्षा-करियर और भविष्य के प्रति अनिश्चितता के माहौल के विस्तार का संकेत है। विश्लेषण से पता चलता है कि 'स्ट्रीट क्राइम' स्थिर हो रहे है, लेकिन 'सॉफ्टवेयर क्राइम' बेकाबू हो रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि सड़क पर रिस्क लेकर छोटे-मोटे अपराध करने वाले अब इंटरनेट पर 'कमाई' में जुट गए हैं। जाहिर है, पुलिस व्यवस्था को अब डंडे से ज्यादा डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा एनालिटिक्स की जरूरत है। वास्तव में, एनसीआरबी के आंकड़े समाज के उस अंधेरे पक्ष को उजागर करने वाले होते हैं, जिनकी अनदेखी के परिणाम समाज को पतन की ओर धकेलने वाले हो सकते है। इन आंकड़ों से इसका भी संकेत मिलता है कि शासन-प्रशासन को किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। बदलते वक्त और समाज के आचरण से अपराध का स्वरूप और प्रवृत्ति बदल रही है। इस बिंदु पर भी जिम्मेदारों का ध्यान देने की जरूरत है।

प्रधानमन्त्री की देश से अपील

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की देशवासियों से मितव्ययिता बरतने की अपील पर राजनीतिक भूचाल जैसा आ गया है क्योंकि विपक्ष इसे सत्तारूढ़ दल भाजपा की चालाकी बता रहा है और कह रहा है कि सरकार ने यह एहसास पांच राज्यों के चुनाव बीत जाने के बाद अपनी सुविधानुसार किया है जबकि आर्थिक मोर्चे पर सावधानी दिखाने का समय विगत मार्च महीने के शुरू से ही प्रारम्भ हो गया था जब ईरान व इजराइल-अमेरिका युद्ध शुरू हुआ था। जाहिर है कि प्रधानमन्त्री ने युद्ध के संकट को देखते हुए ही इस तरह की अपील की है और लोगों से पूरे वर्ष सोने के आभूषण आदि न खरीदने और पैट्रोल व डीजल कम खर्च करने तथा स्वदेशी सामान खरीदने का आह्वान किया है जिससे भारत अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा बचा सके। यह कड़ुवा सत्य है कि भारत प्रतिवर्ष 900 से लेकर एक हजार टन सोने का आयात करता है जिसका मूल्य अरबों डॉलर में जाकर पड़ता है। विश्व स्वर्ण परिषद (वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल) के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण आयात करने वाले देशों में से एक है जहां सोने की मांग अत्यधिक रहती है। इसके कई कारण हैं जिनका खुलासा यहां किया जाना संभव नहीं है परन्तु इतना कहना ही काफी है कि भारत में सोने को भविष्य की पूंजी गारंटी के रूप में लिया जाता है जिसे सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ दिया गया है। विपक्ष यह सवाल भी खड़े कर रहा है कि जिस देश की कुल आबादी 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा हो उस देश में सोना न खरीदने की अपील किन लोगों से की जा रही है? मगर विपक्ष का यह तर्क रहा है कि देश के दस प्रतिशत लोगों का ही इसकी राष्ट्रीय सम्पत्ति के 90 प्रतिशत हिस्से पर अधिकार है। अतः प्रधानमन्त्री की अपील इसी वर्ग से है। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि भारत में आर्थिक गैर बराबरी की खाई बहुत चौड़ी है। जहां तक पैट्रोल व डीजल का सवाल है तो बढ़ते शहरीकरण व उपभोक्तावाद और टेक्नोलॉजी उन्नयन की वजह से पैट्रोल व डीजल का बढ़ता उपयोग गांव से लेकर शहरों तक की जरूरत बन चुका है। भारत के सुदूर क्षेत्रों तक में अब मोटरसाइकिल ने बाइसिकल की जगह ले ली है। इसे हम बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का प्रभाव भी कह सकते है मगर यह एक हकीकत है लेकिन यह भी सच है कि यह मोटर क्रांति विशुद्ध रूप से पैट्रोल आयात पर ही टिकी हुई है। भारत अपने वार्षिक बजट के आधे के मूल्य का प्रतिवर्ष कच्चा तेल आयात करता है अतः इस मद में विदेशी मुद्रा का खर्च सर्वाधिक होता है। दूसरी तरफ युद्ध के डर से भारत में विदेशी मुद्रा की आवक में सिलसिलेवार कमी दर्ज हो रही है मगर ऐसा नहीं है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो। अभी भी भारत के पास 688 अरब डॉलर का यह भंडार है परन्तु मितव्ययिता वक्त की मांग है। इसके साथ ही भारत खाने के तेल का भी भारी मात्रा में आयात करता है क्योंकि इसका उत्पादन मांग के अनुरूप हम नहीं कर पाते हैं अतः श्री मोदी ने इसमें भी बचत करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करने की सलाह भी दी है और इसे राष्ट्र भक्ति से जोड़ा है क्योंकि वह संभावित संकट का समय है। हम जानते है कि ईरान के साथ भारत के सम्बन्ध बहुत ऐतिहासिक व मधुर रहे हैं परन्तु बदलते भू-राजनीतिक कारणों की वजह से इनमें बदलाव आया है। अमेरिका जिस तरह से ईरान पर अपनी दादागिरी चला रहा है उसकी वजह से इस देश की व्यापारिक क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है वरना भारत ईरान से अपनी मुद्रा रुपये में ही तेल खरीदा करता था। परन्तु 2019 से हमने इससे तेल खरीदना बन्द कर दिया है। इसके साथ ही इसके होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री मार्ग के बन्द होने के कारण भारत को आने वाली तेल व गैस सप्लाई पर भी विपरीत असर पड़ रहा है और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन दोनों वस्तुओं के भाव रोजाना महंगे होते जा रहे हैं जिसकी वजह से भारत को अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। इसके समानान्तर भारत को अन्य समुद्री मार्गों से तेल व गैस की सप्लाई लेनी पड़ रही है जिस पर अधिक खर्चा आ रहा है। यह क्रम पिछले तीन महीने से चल रहा है परन्तु भारत में पैट्रोल व डीजल के भाव स्थिर हैं। सरकार ने ये भाव उत्पाद शुल्क में कमी करके थाम रखे हैं। विपक्ष यह भी आरोप लगाता रहता है कि सरकार ने उत्पाद शुल्क की दर बहुत ऊंची रखी हुई है। हालांकि इस बारे में विशेषज्ञों की राय अलग-अलग हो सकती है कि पैट्रोल व डीजल के भाव घरेलू बाजार में स्थिर रखने के लिए उत्पाद शुल्क में घट-बढ़ अन्तर्राष्ट्रीय भावों के समानान्तर होनी चाहिए जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था के मानकों पर विपरीत असर न पड़े लेकिन जहां तक ईंधन गैस का सवाल है तो इसमें सरकार को भारी वृद्धि करनी पड़ी है जिसका असर रोजमर्रा की जिन्दगी पर भी पड़ा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशील एन्क्लेव, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/33863)

फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ऑडिटोरियम में हुआ हॉस्पिटल डे एवं नर्सेस डे-2026 का भव्य आयोजन

गोरखपुर।

फातिमा अस्पताल द्वारा हॉस्पिटल डे एवं नर्सेस डे-2026 का भव्य आयोजन आज दोपहर 2-00 बजे से फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल के वरिष्ठ कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ के समर्पण, सेवा और योगदान को सम्मानित करना रहा। फातिमा हॉस्पिटल में नवनिर्मित 'ऑक्सीजन प्लांट' का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि सिटी एसपी निमिष पाटील द्वारा किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक फादर डॉ. संतोष सेबास्टियन और सिस्टर डॉ. हेलेन मैरी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत फातिमा अस्पताल टीम द्वारा प्रार्थना गीत से हुई। इसके पश्चात अस्पताल के निदेशक फा. डॉ.संतोष सेबास्टियन ने स्वागत संबोधन दिया। इस अवसर पर अस्पताल के निदेशक फा. डॉ. संतोष सेबास्टियन ने अपने संबोधन में कहा कि फातिमा अस्पताल निरंतर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट को आत्मनिर्भरता और आपातकालीन तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया तथा डॉक्टरों, नर्सों एवं समस्त स्टाफ के समर्पण की सराहना की। मुख्य अतिथि डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, माननीय महापौर, गोरखपुर ने अपने संदेश में फातिमा अस्पताल

की सेवा-भावना की सराहना करते हुए अस्पताल के वरिष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री निमिष पाटील , सिटी एसपी , गोरखपुर ने 'ऑक्सीजन प्लांट' का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 'फातिमा फिएस्टा' के अंतर्गत आयोजित विभिन्न श्रेणियों के खेलों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए तथा अस्पताल द्वारा समाज के प्रति निभाई जा रही सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर फातिमा अस्पताल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो का प्रदर्शन भी किया गया।कार्यक्रम में गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समां बांधा। अतिथि सम्मान समारोह में रेव. सिस्टर डॉ. हेलेन मैरी, स्त्र निदेशक जनरल, छ्रह्व, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित करते हुए नर्सों की भूमिका को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताया। केक कटिंग समारोह, समूह नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजन उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का समापन सहयोगी निदेशक फा. शिजो ऑगस्टीन के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। फातिमा अस्पताल प्रबंधन ने इस अवसर पर सभी अतिथियों, कर्मचारियों एवं नर्सिंग स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट और करुणामय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम में अस्पताल की डॉक्टर्स , नर्सिंग अधीक्षक, समस्त विभागाध्यक्ष, एवं स्टाफ उपस्थित रहें। 1995 में स्थापित, फातिमा हॉस्पिटल की सेवाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, पूर्वोत्तर रेलवे, एच.ए.एल., एन.टी.पी.सी., भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गोरखपुर एवं मा. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, उत्तर प्रदेश आदि से इम्पैनल्ड हैं। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ब्लड बैंक, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है।

गोरखपुर को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देंगे मुख्यमंत्री

शनिवार, 16 मई को सीएम योगी करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास

गोरखपुर में वाराणसी रोड पर 392.94 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम

पहली किश्त के 63.39 करोड़ रुपये से शुरू हुआ है निर्माण कार्य

30 हजार दर्शकों की होगी क्षमता, 7 प्लेइंग सहित कुल 11 पिच होगी स्टेडियम में

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देंगे। वह शनिवार (16 मई) को इस अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर - वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदोर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपये की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपये जारी हो चुके है और स्टेडियम बनाने के लिए एलाइनमेंट, मिट्टी भराई, लेवलिंग और बड़े निर्माण उपकरणों को लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। विकास की नजीर पेश कर रहे गोरखपुर को आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जरिये वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भी जाना जाएगा। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। गोरखपुर से पहले यूपी में कानपुर, लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैं, वाराणसी में बन रहा है। मुख्यमंत्री ने जब गोरखपुर में राय का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की मंशा जताई तो सबसे पहली आवश्यकता अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप पर्याप्त भूमि की पड़ी। इसके लिए जिला प्रशासन ने गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदोर में भूमि चिन्हित की। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित किया है। गोरखपुर में बन रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्रफल में आकार लेगा। कुल 30 हजार दर्शक क्षमता का यह स्टेडियम 'ग्राउंड प्लस टू फ्लोर' के हिसाब से बनेगा। इसके ग्राउंड पर खिलाड़ियों के लिए 7 प्लेइंग पिच और 4 प्रैक्टिस पिच होगी। स्टेडियम के पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में प्रत्येक में 14,490 दर्शक बैठ सकेंगे। नार्थ पैवेलियन मीडिया और साउथ पैवेलियन विशिष्टजन के लिए होगा। रात्रिकालीन मैच भी हो सकें, इसके लिए मेन स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानक के चार हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था रहेगी। यहां क्रिकेट के अलावा अन्य बड़े आयोजन भी होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतरीन जगह पर है। गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग फोरलेन से जुड़ा यह स्थान, गोरखपुर एयरपोर्ट से करीब 24 किमी की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से करीब 20 किमी है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए यहां पहुंचना काफी सुगम होगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि ताल नदोर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग पर बहुआयामी विकास का एक नया मॉडल दिखेगा।

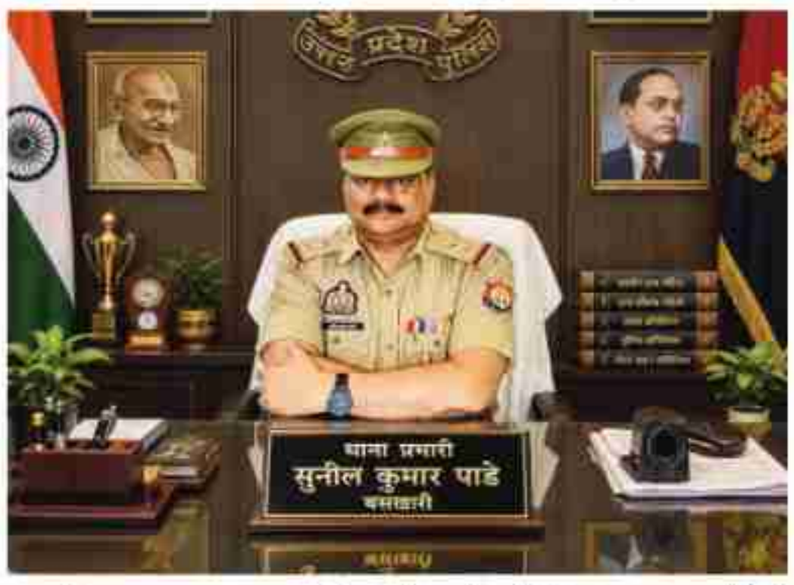

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए चर्चित हैं बसखारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे

अम्बेडकरनगर। जनपद पुलिस में अपनी कर्तव्यनिष्ठा, सख्त कार्यशैली और अपराध नियंत्रण को लेकर पहचान बना चुके बसखारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाकर कानून व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में वह जनपद के लगभग आठ थानों में प्रभारी रह चुके हैं और प्रत्येक स्थान पर उन्होंने अनुशासन एवं सक्रिय पुलिसिंग की अलग पहचान बनाई है। बसखारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे अपराध एवं अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। उनके कार्यक्षेत्र में जुआ तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार छापेमारी और निगरानी के चलते असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय बना हुआ है, जबकि आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हुआ है। सूत्रों के अनुसार, थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उनकी सक्रियता और सख्त रवैये के कारण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बेहतर बनी हुई है। आम जनता भी उनके कार्यों की सराहना कर रही है तथा उन्हें एक ईमानदार, कर्मठ और प्रभावशाली पुलिस अधिकारी के रूप में देखती है।

शादाब हुसैन, फ़ौक बहराइची, शैलेंद्र मिश्रा व ऋचा श्रीवास्तव को अवध वाटिका सम्मान 2026 से किया गया सम्मानित

बहराइच।

वाटिका साहित्य संस्थान बहराइच के तत्वावधान में आयोजित पाक्षिक कवि गोष्ठी का आयोजन सेनानी भवन सभागार बहराइच में किया गया।जिसकी अध्यक्षता पी0के0प्रचंड ने की, संचालन तिलक राम अजनबी ने किया तथा माँ वीणा पाणि की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में अवध वाटिका साहित्य संस्थान बहराइच की ओर से युवा कवयित्री डा0ऋचा श्रीवास्तव को अवध वाटिका हिंदी साहित्य गौरव सम्मान 2026,कवि शैलेन्द्र मिश्रा को अवध वाटिका हिंदी साहित्य गौरव सम्मान 2026,शायर फ़ौक़ बहराइची को अवध वाटिका उर्दू साहित्य गौरव सम्मान 2026 साथ ही पत्रकारिता जगत में 30 वर्षों से निर्भीक पत्रकारिता करने वाले उत्तर प्रदेश जिला मान्यताप्राप्त पत्रकार एसोसियेशन के मण्डल अध्यक्ष शादाब हुसैन को अवध वाटिका पत्रकार गौरव सम्मान 2026 का सम्मान पत्र अंग वस्त्र मेमोंटो संस्था के अध्यक्ष पी0 के0 प्रचण्ड , कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम प्रसाद कौशल , विशिष्ट अतिथि डा0दिनेश त्रिपाठी शम्स , उपाध्यक्ष रईस सिद्दीकी व अन्य सदस्यों ने प्रदान कर सम्मानित किया। तत्पश्चात कवि विनोद कश्यप, सुनील कुमार, शैलेन्द्र मिश्रा, अब्दुल रफी खान बम्पर बहराइची, कलीम खान ,विनोद पाण्डेय ,फौक बहराइची, रईस सिद्दीकी, डा0ऋचा श्रीवास्तव, डा0दिनेश त्रिपाठी शम्स,विनोद पाण्डेय,सेनानी भवन प्रभारी रमेश चन्द्र मिश्र सहित सभी कवियों व शायरों ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीराम प्रसाद कौशल ने तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के संगठन मंत्री रमेश चन्द्र मिश्र ने सभी कवि एवं साहित्य प्रेमी बंधुओं की सराहना की तथा आशीर्वचन प्रदान किया। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पी0के0प्रचंड ने अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए पढ़ा-सालगिरह की मिली बधाई व्हाट्स अप पर। डिब्बा भरके मिली मिठाई व्हाट्स अप पर। ऐ बड़कऊ तुम्हीं बतावौ अब हमका, येहिका हम कैसे अब खाई व्हाट्स अप पर। इस अवसर पर आलोक शुक्ला एडवोकेट, सहित अन्य साहित्य प्रेमी बंधु उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम का आनन्द प्राप्त किया।

दो फोटो पत्रकार दुनिया से हो गये रुखसत

पत्रकारों एवं छायाकारों ने व्यक्त की शोक संवेदना

फतेहपुर। जिले की पत्रकारिता में फोटो पत्रकार के रूप में अपना-अपना लोहा मनवाने वाले दो फोटो पत्रकार दुनिया से रुखसत हो गये। जानकारी के अनुसार आर के सोनी अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। रास्ते में उनकी तबियत बिगड़ गई। उपचार के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान ही उनका निधन हो गया। अन्तिम संस्कार भिटौरा में किया गया। आर के सोनी के बाद फोटो पत्रकार सिराज अल्वी भी दुनिया से रुखसत हो गये। जो काफी समय से बीमार थे। जिला अस्पताल के निकट स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। पत्रकारों एवं छायाकारों ने शोक संवेदना व्यक्त की।

एनसीआरबी रिपोर्ट पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली को बताया अपराध की राजधानी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2024 रिपोर्ट को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट तो एक साल पुरानी है, जबकि मौजूदा समय में राजधानी की कानून व्यवस्था उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध रोकने वाली पुलिस ही अब खुलेआम गोली मारकर हत्याएं कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण दिल्ली अपराध के मामलों में देश के 19 महानगरों में सबसे ऊपर पहुंच गई है. देवेंद्र यादव ने कहा कि एनसीआरबी रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दहेज हत्या के 109 मामले, रेप के 1058 मामले, घरेलू हिंसा और क्रूरता के 4646 मामले, अपहरण के 3974 मामले और यौन उत्पीड़न के 316 मामले दर्ज किए गए. प्रति एक लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 176.8 दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि दहेज हत्या के मामलों में लगातार भयावह तस्वीर सामने आ रही है. साल 2023 में 114 और 2022 में 129 महिलाओं की दहेज के कारण हत्या हुई थी. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि राजधानी में प्रति लाख आबादी पर संगीन अपराधों की दर 1688 है, जो देश के सभी महानगरों में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि साल 2024 में दिल्ली में 2 लाख 75 हजार 402 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस केवल 31.9 प्रतिशत मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल कर सकी, जो देश के सभी महानगरों में सबसे कम है.उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस अपराधियों के खिलाफ समय पर चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पा रही, तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा. यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और दिल्ली अपराध में नंबर वन बनती जा रही है. देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में हत्या, रेप, लूट, साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध और नशे के कारोबार जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके साथ ही अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि आईपीसी और बीएनएस के तहत न्याय के लिए साल 2024 में 4 लाख 34 हजार 981 मामले लंबित रहे. उन्होंने कहा कि पूरे साल में केवल 50 हजार 305 मामलों का ट्रायल पूरा हो सका, जबकि 88.3 प्रतिशत मामले अब भी अदालतों में अटके हुए हैं. ट्रायल पूरे होने वाले मामलों में कुल सजा दर 74.1 प्रतिशत रही, लेकिन रेप मामलों में सजा दर सिर्फ 24.1 प्रतिशत दर्ज की गई. वहीं यौन उत्पीड़न के मामलों में किसी को भी सजा नहीं मिलना बेहद चिंताजनक बताया गया. कांग्रेस नेता ने कहा कि आर्थिक अपराधों के 25 हजार 532 लंबित मामलों में केवल 4524 मामलों की सुनवाई हो सकी और इनमें सजा की दर 27.3 प्रतिशत रही.

अन्नाद्रमुक में दोफाड़- बागी विधायकों ने जड़े पलानीस्वामी पर गंभीर आरोप, बोले- हमें पार्टी से निकालना अवैध

चेन्नई । अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) में अंदरूनी कलह अब दोफाड़ होने की स्थिति में खुलकर सामने आ गई है। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने बुधवार को पार्टी के बागी नेताओं एसपी वेलुमणि, सीवि षणमुगम और सी विजयभास्कर को उनके पदों से हटा दिया। पलानीस्वामी की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सीवि षणमुगम ने इसे अवैध बताया है। पलानीस्वामी ने बागी विधायकों पर कार्रवाई की है, जिनमें वरिष्ठ नेता नथम आर विश्वनाथन भी शामिल हैं। इन विधायकों ने तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत के दौरान टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान करके पार्टी के निर्देश का उल्लंघन किया था। इसके बाद पलानीस्वामी ने 12 बागी विधायकों और उनके समर्थकों को पार्टी के विभिन्न पदों से हटाकर नए जिला सचिवों की नियुक्ति की है। एआईएडीएमके नेता ने पलानीस्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा, «अगर हमने कुछ गलत किया होता, तो पार्टी के महासचिव के तौर पर उन्हें (पलानीस्वामी) हमसे बात करनी चाहिए थी और पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन पलानीस्वामी ने महासचिव के रूप में अपने चार साल के कार्यकाल में सिर्फ पार्टी और पार्टी पदों से बर्खास्तगी का काम किया है। उन्होंने कहा, जो भी उन पर सवाल उठाता है, उसे पद से और यहां तक कि पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हमारे 26 पार्टी पदाधिकारियों को उनके पदों से बर्खास्त किया है। उन्हें इतनी शक्ति किसने दी? उनके पास कोई शक्ति नहीं है और उनके द्वारा जारी किया गया बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा। पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके की मूल नीति को कमजोर कर दिया है। सीवि षणमुगम ने कहा, «पलानीस्वामी ने डीएमडीके को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। हमने उसी समय उनके इस रुख का विरोध किया था। इसीलिए वे हमारे गठबंधन से अलग हो गए। फिर भी उनकी पहली पसंद एआईएडीएमके ही थी, लेकिन पलानीस्वामी ने मना कर दिया। वे अपनी बात पर अड़े रहे। अब एआईएडीएमके को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। आज हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं।»

हार की जिम्मेदारी लेने से बच रहे ईपीएस

एआईएडीएमके नेता ने कहा, आज जब ईपीएस से पूछा जाता है कि हम क्यों हारे, तो वे पूछते हैं, क्या पार्टी 1996 में नहीं हारी थी? क्या हम 2006 में भी नहीं हारे थे? जी हां, हम हारे थे। लेकिन पुरची थलाइवी अम्मा में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की क्षमता थी। हर हार के बाद, अम्मा घोषणा करती थीं कि वे एमजीआर के शासन को फिर से स्थापित करेंगी और वे पार्टी को दूसरी बार सत्ता में लाने में सफल रहीं।

षणमुगम बोले- अवैध है कार्रवाई

पार्टी की ओर से जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने तत्काल प्रभाव से 26 विधायकों को सभी पार्टी पदों से बर्खास्त करने की घोषणा की। पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए षणमुगम ने कहा कि उन्हें हटाना अवैध है। उन्होंने कहा कि पार्टी महासचिव ने कार्रवाई शुरू करने से पहले उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था। एआईएडीएमके नेता ने कहा, उन्हें (ईपीएस को) हमें पार्टी पदों से बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बर्खास्तगी वैध नहीं है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। एआईएडीएमके की आम सभा में भाग लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता।

यूपी- प्रदेश में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, 62 लोगों की दर्दनाक मौत

कई जिलों में पंगु हुई बिजली व्यवस्था

लखनऊ। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी-पानी की चपेट में आने से अलग-अलग जिलों में 62 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। मरने वालों में भदोही में 11, मिर्जापुर में 6, सीतापुर में 2, कानपुर मंडल में 14, प्रयागराज में 9, प्रतापगढ़ में 4, रायबरेली में 2, संभल में दो और बरेली में 14 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिला अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा रहा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म

प्रदेश में एक ओर जहां आंधी बारिश से नुकसान के अलावा गर्मी से कुछ राहत मिली वहीं बुंदेलखंड समेत दक्षिणी जिलों में तेज धूप और भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। बांदा 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। इसके अलावा झांसी में 44.5, प्रयागराज में 43.5, हमीरपुर में 43.2 और उरई में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बृहस्पतिवार से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। 16 मई से बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में लू चलने और तपिश बढ़ने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में वाहनों की संख्या हुई कम; दो गाड़ियों के साथ जाते दिखें पीएम

नई दिल्ली। दुनियाभर में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कमी किए बिना प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटा दी गई है। एक वीडियो में पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखीं। सरकार के इस कदम को ईंधन बचत और खर्च नियंत्रण की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल जरूरी सुरक्षा और संचालन से जुड़े वाहन ही प्रधानमंत्री के काफिले का हिस्सा होंगे।

सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह पूरी तरह मजबूत रहेगी। एसपीजी प्रोटोकॉल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम पहले की तरह लागू रहेंगे। हालांकि, अनावश्यक वाहनों को हटाकर काफिले को अधिक व्यवस्थित और ऊर्जा-कुशल बनाने पर जोर दिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सुझाव दिया है कि जहां संभव हो, काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। हालांकि इसके लिए नए वाहन खरीदने के बजाय मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया है। सरकार के इस कदम को पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।

भाजपा शासित राज्यों में भी दिखने लगा असर

प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का असर भाजपा शासित राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित अन्य नेताओं ने भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला- सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को फिर मिला सेवा विस्तार, लगातार दूसरी बार बढ़ा कार्यकाल

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया। सूद ने 25 मई 2023 को दो वर्ष की अवधि के लिए सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था। इससे पहले भी उनको एक साल के सेवा विस्तार दिया गया था। अब वह इस पद पर मई 2027 तक बने रहेंगे।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है। यह उनके कार्यकाल में दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले मंगलवार को अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पीएमओ में बैठक हुई थी। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे।

मई 2027 तक बने रहें सीबीआई निदेशक

केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल फिर से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया। सूद ने 25 मई 2023 को दो वर्ष की अवधि के लिए सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था। इससे पहले मई 2025 में भी उनको एक साल के सेवा विस्तार दिया गया था, अब वह इस पद पर मई 2027 तक बने रहेंगे। सरकार की ओर से जारी बयान में मुताबिक, उनके कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई चयन समिति की बैठक में लिया गया। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों की मंत्रिमंडलीय समिति (एसीसी) ने एक वर्ष की अवधि के लिए सूद के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी।

चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने जताई थी आपत्ति

बैठक के बाद राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए असहमति नोट दर्ज कराया। राहुल गांधी ने कहा कि वह ऐसी चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जिसमें निष्पक्षता पर सवाल उठते हों।

कई हाई-प्रोफाइल मामले संभाल चुके हैं प्रवीण सूद

प्रवीन सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किए जाने से पहले कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में कार्यरत थे। सूद का जन्म 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है।

इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बेंगलुरु और न्यूयॉर्क स्थित मैक्सवेल स्कूल ऑफ गवर्नेंस, सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। सूद ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की निगरानी की। तकनीक-प्रेमी सूद कर्नाटक में न्यायपालिका के साथ मिलकर सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) और आईसीजेएस (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) को मजबूत करने की दिशा में भी कार्य कर चुके हैं।

राहुल-प्रियंका को धमकी, वायनाड को बना देंगे अमेठी, अगर केरलम के मुखमंत्री बने केसी वेणुगोपाल

नई दिल्ली केरलम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हफ्ताभर से ज्यादा हो गया है लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है. केरलम में मुख्यमंत्री पद को लेकर तीन दावेदार हैं और तीनों के साथ कांग्रेस हाईकमान बैठक कर रहा है लेकिन एक नाम को लेकर अब तक एक राय नहीं बन सकी है. इस बीच वायनाड में कुछ पोस्टर लगे हैं, जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को धमकी दी गई है. इसमें धमकी देते हुए लिखा है कि अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वायनाड को अगला अमेठी बना देंगे. हैरान करने वाली बात ये है कि ये पोस्टर कहीं और नहीं, बल्कि जिला कांग्रेस के दफ्तर में लगाए गए हैं. इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सीधी-सीधी धमकी दी गई है. इनमें से एक पोस्टर में लिखा है- वायनाड अगला अमेठी होगा. कुछ पोस्टरों में राहुल और प्रियंका वायनाड को भूल गए हैं. आप यहां से दोबारा नहीं जीतेंगे और राहुल जी, केसी शायद आपका बैग उठाते होंगे लेकिन केरल के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे लिखा है. एक पोस्टर में तो सीधे-सीधे ये लिखा है- आरजी और आरजी, ये चेतावनी नहीं है. केरल आपको इस भयानक भूल के लिए कभी माफ नहीं करेगा.

कहां फंस रहा है मामला?

केरलम में 4 मई को चुनाव नतीजे आए थे. इसमें कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीती थीं. लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला नहीं हो पाया है.सत्ता के लिए केरलम कांग्रेस के तीन नेताओं के बीच खींचतान चल रही है. इनमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला हैं. मंगलवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरलम कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत की थी लेकिन फैसला नहीं हो पाया.हालांकि, माना जा रहा है कि जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे वेणुगोपाल की स्थिति मजबूत होती जा रही है. कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा विधायक वेणुगोपाल के समर्थन में हैं. लेकिन यहीं मामला फंस गया है. जहां एक ओर यह माना जाता है कि वेणुगोपाल को राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा हासिल है, वहीं दूसरी ओर सतीशन पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के एक तबके के बीच भावनात्मक रूप से ज्यादा लोकप्रिय बनकर उभरे हैं.

होर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ा 15वां एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन, भारतीय नौसेना बनी सुरक्षा कवच

नई दिल्ली।

फारस की खाड़ी से भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है और अब भारत की ओर बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जहाज की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां लगातार सहयोग कर रही हैं। जानकारी के अनुसार, यह भारत के लिए रवाना होने वाला 15वां एलपीजी जहाज है जिसे फारस की खाड़ी क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया है। मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच इस अभियान को काफी अहम माना जा रहा है।

मल्टी-एजेंसी ऑपरेशन से मिली सफलता

सूत्रों के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन का परिणाम है। भारतीय नौसेना ने इस अभियान में अहम भूमिका निभाते हुए जहाजों को आवश्यक सुरक्षा और एस्कॉर्ट प्रदान किया। एक अधिकारी ने बताया कि 15वां जहाज पहले ही होर्मुज पार कर चुका है और अंतिम जहाज भी सुरक्षित मार्ग पर है।

भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति मजबूत

हाल के दिनों में भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार गश्त और एस्कॉर्ट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब कई देश ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक शिपिंग रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं।

आज होगा केरल के नए सीएम का एलान- कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी; कई दौर की बैठक के बाद मंथन पूरा

नई दिल्ली। केरल में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी चर्चाएं और आंतरिक बैठकें पूरी कर ली हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी कि इस मुद्दे पर अब अंतिम निर्णय कल घोषित किया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि केरल कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों की मंजूरी के बाद पार्टी हाईकमान ने सभी जरूरी विचार-विमर्श पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा कल सार्वजनिक रूप से की जाएगी। इसके साथ ही केरल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने की संभावना है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने घोषणा की है कि कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक गुरुवार, 14 मई को आयोजित की जाएगी। यह बैठक केपीसीसी मुख्यालय में होगी, जिसमें पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेतृत्व के अनुसार, केरल में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी के भीतर व्यापक चर्चा हुई है। अब यह निर्णय पूरी तरह अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पार्टी का कहना है कि सभी संबंधित नेताओं से विचार-विमर्श के बाद एक नाम पर अंतिम सहमति बनाई गई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कल की जाएगी।

प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा- शरीर पर मिले छह चोट के निशान, जो 5-7 दिन पुराने

लखनऊ । सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। विसरा रिपोर्ट के बाद और चीजें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और सामने आई है। जो कई सवाल खड़े कर रही है। प्रतीक की बॉडी पर छह चोट के निशान मिले हैं, इनमें तीन चोट पांच से सात पुरानी है और तीन चोट एक दिन पुरानी है। हालांकि इनका उनकी मौत से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन, ये चोट उनको कैसे लगी है, ये पता नहीं चल सका है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे। इसी वजह से हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे मौत हुई। हार्ट और फेफड़ों से मिले खून के थक्कों के नमूनों को आगे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। शरीर के अंदरूनी अंगों को भी केमिकल जांच के लिए प्रीजर्व किया गया है। शरीर पर मिले सभी चोट के निशान मौत से पहले के

बताए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ऐसी गंभीर स्थिति है, जिसमें खून के थक्के फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं। इससे सांस लेने और शरीर में खून का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होता है। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता रविदास मेहरोत्रा ने युवक प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, हम प्रतीक यादव की असामयिक और अचानक मृत्यु से बेहद दुखी और आहत हैं। प्रतीक यादव को अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। यह संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत है। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और शरीर के अंदर जहर मिला था। इसलिए उनका पोस्टमार्टम कराया गया। प्राकृतिक मौत में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। पोस्टमार्टम के बाद शव को 5 घंटे तक मोर्चरी में रखा गया। हमने मौत के कारणों की जांच कराने की मांग की है। डॉक्टरों ने भी बताया कि शरीर पर चोट के निशान थे और शरीर नीला पड़ गया था, जो जहर दिए जाने का संकेत देता है। शव को अब उनके आवास पर रखा गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि मौत सामान्य नहीं थी। हमने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से प्रतीक यादव की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।